

राज्यसभा का 267वां सत्र अनिवार्यताकाल के लिए स्थगित, 119 प्रतिशत कामकाज हुआ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भारत। राज्यसभा की कार्यवाही शून्यकारों को अनिवार्यता के लिए रथगति कर दी गयी तथा सत्र के दौरान उत्तर सदन में 119 प्रतिशत कामकाज हुआ।

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उत्तर सदन के 267वें सत्र को अनिवार्यता के लिए रथगति करने से पहले अपने पारंपरिक संबोधन में कहा कि इस दौरान सदन में वक्तव्य (संशोधन) विधेयों पर कामकाज कर्त्तव्य है। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान 159 घंटे में 119 प्रतिशत कामकाज हुआ। इस सत्र में 49 नियम विधेयक पेश किए गए। उन्होंने कहा कि इस सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अधिभाषण

के धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर लेखी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति के अधिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा तीन दिन तक चली और इसमें 73 सदस्यों ने हिस्सा लिया। सभापति ने बताया कि बजट 2025-26 पर भी तीन दिन तक चर्चा हुई जिसमें 89 सदस्यों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद सत्र ही चार महत्वपूर्ण मंत्रालयों—गृह, मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रेल मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा हुई।

धनखड़ ने कहा कि तीन अप्रैल को उत्तर सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होकर अगले दिन यारी चार अप्रैल को सुहृद चार बज बज दो बिंदी के लिए तक चली जो अब तक की सबसे लंबी बैठक थी। उन्होंने सभापति ने कहा कि इस सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अधिभाषण



इतिहास में सबसे अधिक लंबे समय तक चली कार्यवाही है। इससे लोगों तक बहुत अच्छा संदेश गया। उन्होंने कहा कि इस बैठक के दौरान, सदन ने परिवर्तनकारी वक्तव्य (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी दी जिसमें समानता और स्थान के विवरों में कायम रखने के लिए बहुत संपर्क संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही के प्राप्तधान है। सभापति ने कहा कि यह सत्र अपनी ऐतिहासिक विधेयों और एकता की भवानी के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने

कहा कि यह भारत की संसदीय यात्रा में एक नियांयक क्षण रहा और इसने याद लिया कि संवाद और साझा मकान के माध्यम से क्या हासिल किया जा सकता है।

इस सत्र के दौरान सदन में वक्तव्य (संशोधन) विधेयक 2025, आपास प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024, बैंककारी विधेयां (संशोधन) विधेयक 2024, बैंककारी विधेयक 2025, वेलेक्षन (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक 2024, बायुयान वस्तुओं के पुष्टि के लिए एक सार्विक संकाय सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया गया और शुक्रवार तक तक रीवाच चार बजे इस संकाय को धनियमत से मंजूरी दी गई। गोलराम है जिस सदन के लिए एक शुक्रवार तक चला गया और शुक्रवार तक रीवाच चार बजे इस संकाय को धनियमत से शुरू हुआ।

विभुन सदन की शुरूआत 31 दूसरे चरण 13 मार्च से शुरू हुआ।



त्रिवेणी संगम से 1,000 बोतल गंगा जल जर्मनी भेजा गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गंगा जल की पैकेजिंग की शुरूआत महिला स्ट्रिंग सहायता समूह की तरफ से की गई थी।

प्रयागराज में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका प्रयागराज के परिवर्तनी संगम के जल की विदेशों में बढ़ती मांग के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को कहा कि गंगा जल की 1,000 बोतलों की पाली खेप जर्मनी भेजी गई थी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बयान में कहा कि 13 जनवरी से

26 फरवरी तक यहां आयोजित महाकुंभ मेले में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लाई। बयान में खेप जर्मनी की विवेणी के पावन जल की डुबकी से लोक गंगा जल की 50,000 बोतल में नगपूर के शिव शंभु मूर्ति सोसायटी को 50,000 बोतल विवेणी का जल भेजा गया।

उन्होंने बताया कि श्री पंच दशनाम जुना अश्वाधे के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लाई। बयान में खेप जर्मनी की अनुवाद मांगों पर चर्चा की गई, जिसके बाद अनुदान मांगों को पारित कर दिया गया।

दशनाम में खेप जर्मनी के जल भेजा गया है, जबकि जर्मनी के लिए 250 मिलिलीटर की बोतल में गंगा जल की खेप भेजी गई।

बजट सत्र में लोकसभा ने 16 विधेयक पारित किये, 118 प्रतिशत हुआ कामकाज

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भारत। संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा की कुल 26 बैठकें हुईं और इस दौरान लोकसभा की (संशोधन) विधेयक सहित 16 विधेयक पर कामकाज हुआ। लोकसभा संविधानांकन विभाग ने शुरू कर दिया। उनकी सुरक्षा की समीक्षा के बाद यह कदम उठाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री की पहली होने के कारण उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री थी। मनमोहन सिंह की लिए साल 26 दिवसरक्त को 92 वर्ष की आयु में नियम हो गया था।

सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों द्वारा कोर की सुरक्षा की समीक्षा के बाद उन्हें 'श्रेणी' के तहत राजा जारी दिया गया है, जो सुरक्षा को दूसरा सर्वोच्च रैंक देता है। उन्होंने कहा कि इसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व बैंक (सीआरएफ) वीआईपी सुरक्षा कर्मी को जारी किया। उनकी सुरक्षा के बारे में श्रेणी के अन्तर्गत और प्रोटोकॉल की संदर्भ में श्रेणी की अपीली जारी की गयी है।

सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए विशेष सुरक्षा समूह अविभागी के बदला के बाद, सिंह को 2019 में सीआईएफ के एडवर्सल सेक्यूरिटी लाइज़न (एसएल) प्रोटोकॉल के साथ जेड-लॉस कार्यक्रम के बाद अप्रैल 2024 और 2014 के बीच दो कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री रहे। केंद्रीय सुरक्षा सूची के तहत वीआईपी सुरक्षा कर्व उत्तर जेड-प्लस (एसएल) से शुरू होकर जेड-प्लस, जेड, वाई-प्लस, वाई और एक्स्प्रेस तक होता है।

सूत्रों ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ-साथ उनके की सुरक्षा की लाभगत एवं दर्जन साथसाहेदारी की जारी रही। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के वर्किंग कार्यक्रम में बदलाव के कारण सिंह परिवार के लिए स्पेशल सुरक्षा अधिकारी रिजर्व बैंक (सीआरएफ) के लिए विशेष सुरक्षा की सुरक्षा कर्मी को जारी किया।

सूत्रों ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ-साथ उनके की सुरक्षा की लाभगत एवं दर्जन साथसाहेदारी की जारी रही। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के वर्किंग कार्यक्रम में बदलाव के कारण सिंह परिवार के लिए स्पेशल सुरक्षा अधिकारी रिजर्व बैंक (सीआरएफ) के लिए विशेष सुरक्षा की सुरक्षा कर्मी को जारी किया।

सूत्रों ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ-साथ उनके की सुरक्षा की लाभगत एवं दर्जन साथसाहेदारी की जारी रही। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के वर्किंग कार्यक्रम में बदलाव के कारण सिंह परिवार के लिए स्पेशल सुरक्षा अधिकारी रिजर्व बैंक (सीआरएफ) के लिए विशेष सुरक्षा की सुरक्षा कर्मी को जारी किया।

सूत्रों ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ-साथ उनके की सुरक्षा की लाभगत एवं दर्जन साथसाहेदारी की जारी रही। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के वर्किंग कार्यक्रम में बदलाव के कारण सिंह परिवार के लिए स्पेशल सुरक्षा अधिकारी रिजर्व बैंक (सीआरएफ) के लिए विशेष सुरक्षा की सुरक्षा कर्मी को जारी किया।

सूत्रों ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ-साथ उनके की सुरक्षा की लाभगत एवं दर्जन साथसाहेदारी की जारी रही। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के वर्किंग कार्यक्रम में बदलाव के कारण सिंह परिवार के लिए स्पेशल सुरक्षा अधिकारी रिजर्व बैंक (सीआरएफ) के लिए विशेष सुरक्षा की सुरक्षा कर्मी को जारी किया।

सूत्रों ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ-साथ उनके की सुरक्षा की लाभगत एवं दर्जन साथसाहेदारी की जारी रही। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के वर्किंग कार्यक्रम में बदलाव के कारण सिंह परिवार के लिए स्पेशल सुरक्षा अधिकारी रिजर्व बैंक (सीआरएफ) के लिए विशेष सुरक्षा की सुरक्षा कर्मी को जारी किया।

सूत्रों ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ-साथ उनके की सुरक्षा की लाभगत एवं दर्जन साथसाहेदारी की जारी रही। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के वर्किंग कार्यक्रम में बदलाव के कारण सिंह परिवार के लिए स्पेशल सुरक्षा अधिकारी रिजर्व बैंक (सीआरएफ) के लिए विशेष सुरक्षा की सुरक्षा कर्मी को जारी किया।

सूत्रों ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ-साथ उनके की सुरक्षा की लाभगत एवं दर्जन साथसाहेदारी की जारी रही। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के वर्किंग कार्यक्रम में बदलाव के कारण सिंह परिवार के लिए स्पेशल सुरक्षा अधिकारी रिजर्व बैंक (सीआरएफ) के लिए विशेष सुरक्षा की सुरक्षा कर्मी को जारी किया।

सूत्रों ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ-साथ उनके की सुरक्षा की लाभगत एवं दर्जन स



सुविचार

कुछ सच तो हम पहले से जानते थे,
बस देखना चाहते थे कि लोग
झूठ कहाँ तक बोल सकते हैं!

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

संतान से पहले संसाधन जरूरी

इन दिनों कुछ मुख्यमंत्री और उनकी पार्टियों के नेता 'जनसंख्या बढ़ाने की अपील' की वजह से सोशल मीडिया पर खबर चर्चा में हैं। वे लोगों से बार-बार कह रहे हैं कि उन्हें अधिक संतानोंपति करनी चाहिए। हालांकि रोजगार की क्या स्थिति है, जिकिस्ता सुविधाएं केसी हैं, परेवहन सुविधाओं का क्या हाल है... इन पर वे बात नहीं करते। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें इन बातों की खास चिंता भी नहीं है। वे इस बात को लेकर किसी भी विवरण नहीं देते। लोकसभा के सींस कमन हो जाए। क्या इसका एकमात्र सम्बन्धन यह है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस दुनिया में लाया जाए? इनमें कोई संदेह नहीं कि कुछ राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में बहुत अच्छा काम किया है। वहां अन्य राज्यों की तुलना में आम आदमी की जिंदगी कुछ बेहतर हुई है। जिन राज्यों में टीएफआर (फुल प्राविन्दन दर) ज्यादा है और लोकसभा में उनके प्रतिनिधि ज्यादा हैं, वहां भी लोग मांग कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को 'इनाम' मिला जाए। इनके उल्लंघन, लोगों से जनसंख्या की अपील करने के भयानक परिणाम हो सकते हैं। क्या हमारा पास बुनियादी सुविधाएं देने के लिए इतने संसाधन हैं? नेताओं को ऐसी अपील करने से पहले आम आदमी के नजरिए को समझना होगा। क्या आप हर बच्चे के लिए साफ हवा, रख्च पेयजल और पोषण आहार सुनिश्चित कर सकते हैं? क्या आप हर बच्चे को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं? क्या आप ऐसा समाज बना सकते हैं, जहां भ्राताचार और अपराधों पर कड़ा किसी नियंत्रण हो और आम आदमी के साथ बेटरीन इताज हो और लोगों को अपनी जेब की चिंता न करनी पड़े?

ये तो चंद सवाल हैं। हकीकत यह है कि लोगों की जिंदगी से जुड़े संघर्ष कम होने का नाम नहीं ले रहे। कमजूर और साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के बच्चे पहले ही बहुत ज्यादा बद्ध होते हैं। परिवारों में अच्छे प्रत्येक लोगों का दबाव अपनी जगह है। जब कोई लोगों से निकलते हैं, तब नवा दबाव आता है कि असली परिश्रद्धा तो हो जाने वाली है। बड़े-बड़े डिग्गीधारी बोरोजगार बैठे हैं। जिन्हें कहीं रोजगार मिल गया है, उनमें से ज्यादातर का वेतन बहुत कम है। युवाओं की उर्जा का काफ़ी हिस्सा तो रोजगार ढूँढ़ने में खर्च हो रहा है। जो लोग इस दुनिया में आ चुके हैं, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए अच्छे रखूँतों की कमी है, सरकारी अस्पताल संसाधनों की कमी से ज़्यादा है, बसों, ट्रेनों में भीड़ ही भीड़ है, शहर में ऐसी जगह मिलना मुश्किल है जहां इन्स्ट्रुमेंट आधा घंटा बैठकर सुनून से सांस ले सके... क्या ये सभी बिंदु इस बात का समर्थन करते हैं कि जनसंख्या में तेज बढ़ोत्तरी होनी चाहिए? पहले इन लोगों की प्रियों तो सुधार दें, इनका भाभा कर दें। नेताओं द्वारा ऐसी अपीलों के साथ सोशल मीडिया पर अमेरिका के एक मशहूर उद्योगपति काफ़ी चर्चा में हैं। वे दुनिया के पांच सबसे अमीरों में शुमार किए जाते हैं। उन्हें इस बात की बहुत चिंता है कि टीएफआर और साधारण आर्थिक प्रदर्शन का असरित संकरण में पड़ जाएगा! हालांकि कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि उद्योगपति आम लोगों से जनसंख्या बढ़ाने की अपील करने वाले को लिये कर रहे हैं, किंतु उन्हें कम वेतन पर नियंत्रण देने के लिए अच्छे रखने के लिए उनका कारोबार खूब चलता रहे। इसी तरह, जनसंख्या बढ़ाने की अपील करने वाले नेताओं की यह कहते हैं कि उन्हें अपना बोर्डें बढ़ाने की चिंता है। अगर किसी नेता या पार्टी को आम जनता की बहुत चिंता है तो पहले उसकी भलाई के लिए काम करें, गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं का इंतजाम करें। उसके बाद यह यह फेसला लोगों पर छाड़ दें कि वे कितनी संतान चाहते हैं।

ट्रीटर टॉक



संसद के दोनों सदनों से वक्फ (संसाधन) विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक का पारित होना देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यह सामाजिक-आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को समान लाता है।

नेत्रन्द्री भोजी

निष्पक्ष जांच और न्याय क्यों नहीं? यूपीएससी की तैयारी कर रहे भीलवाड़ा के राजकुमार जाट की गुजरात के राजकोट में नृशंस हथा को एक नृहीना बीत गया। लेकिन हौरानी की बात है कि भाजपा के एक प्रावधासाली नेता ने खेटे को बचाने के लिए पुलिस पर दबाव बनाकर एकाईआर तक दर्ज नहीं होने दी।

गोविंद सिंह डोटासरा

आज मुख्यमंत्री नियास पर राजस्थान के युवा वर्ग के लिए प्रक्रियाधीन भित्तियों एवं आगामी वर्षों में को जाने वाली संभावित भित्तियों के संबंध में बैठक ली। इस दोस्रा उपस्थिति अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया को पारवर्तित बनाए रखने पर युवाओं के हित में नियुक्ति प्रयोग को समर्पण रुप से संबलित करने हेतु उन्हि दिवस-निवेदा दिया।

भजनलाल शर्मा

प्रेरक प्रसंग

सौ का नोट

एक अंधा व्यक्ति रोज शाम को सड़क के किनारे खड़े होकर भीख मांग करता था। जो थोड़े-बहुत प्यासे भील जाते उसी से अपनी गुजर-बसर किया करता था। एक शाम वहां से एक बहुत बड़े ईस्स गुजर रहे थे। उन्होंने उस अंधे को देखा और उन्हें अंधे की फटेहाल होने पर बहुत दया आई और उन्होंने उस अंधे को नोट उसके हाथ में रखते हुए आगे की राह ली।

उस अंधे आदिने ने भोट को देखा और उसे लगा कि उसी को आदमी ने उसके साथ तो भोट को देखा और उसने नोट को खिल दिया।

एक सज्जन पुरुष जो वहाँ खड़े थे दूश्य देख रहे थे, उन्होंने नोट को उठाया और अंधे व्यक्ति को देते हुए कहा- यह सो रुपये का नोट है। तब वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने अपनी आवश्यकताएँ पूरी की।

